भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1600
31 जुलाई, 2026 को जवाब दिया

भारत को वैश्विक चक्रीय वस्त्र पुनर्चक्रण केंद्र के रूप में विकसित करना

1600. श्रीमती सुधा मूर्तीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने वस्त्र अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला (टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन) संबंधी रिपोर्ट में निर्धारित अल्पकालिक (0-2 वर्ष) लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु, जिसमें अंतर-मंत्रालयी कार्यबल की स्थापना भी शामिल है, एक प्रचालन रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) पानीपत तथा तिरुप्पुर में प्रस्तावित अल्पकालिक नयाचार पुनर्चक्रण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना उन्नयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार वस्त्र अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में भारत की वर्तमान उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए, संधारणीय वस्त्रों के लिए भारत को एक उच्च मूल्य वैश्विक प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करने और शिप ब्रेकिंग के क्षेत्र में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति के समान एक सुव्यवस्थित एवं राजस्व सृजन करने वाला आर्थिक तंत्र विकसित करने का विचार रखती है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय ने "भारत में वस्त्र अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला की मैपिंग" नामक शीर्षक से एक अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट में उन कपड़ों के कचरे का अनुमान लगाया गया है जो ग्राहकों तक पहुंचने से पहले (जैसे कारखारों का कचरा) तथा ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल के बाद फेंके जाने से पैदा होता है। कुल वस्त्र अपशिष्ट का 70 प्रतिशत से अधिक वर्तमान में रिकवर किया जाता है और रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, डाउनसाइकलिंग या पुन: उपयोग करने के लिए भेजा जाता है। निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि लगभग 95 प्रतिशत प्री-कन्ज्यूमर वस्त्र अपशिष्ट को रिकवर किया जाता है, जो मूल्य श्रृंखला में रिकवरी नेटवर्क की मजबूती को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) टास्क फोर्स का गठन किया है, जो सस्टेनेबल उत्पादन, प्रमाणन, निर्यात आदि से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। टास्क फोर्स ने विभिन्न उद्योग केंद्रित कार्यक्रमों को सुगम बनाया है, जो सर्कुलर संवाद और

क्लस्टर एक्सचेंज मैकेनिज्म सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से सर्वोत्तम पद्धतियों और ज्ञान के आदान-प्रदान पर फोकस करते हैं।

केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में, माननीय वित्त मंत्री ने पानीपत और तिरुप्पुर सहित पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सस्टेनेबल वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए "टेक्स-इको पहल" लागू करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों, वस्त्र अनुसंधान संघों, उत्कृष्टता केंद्रों, उद्योग, स्टार्ट-अप और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डरों के सहयोग से वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधन, रिसाइकलिंग और मूल्य संवर्धन सहित सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करना है, साथ ही त्याग किए गए वस्त्रों से रिसाइकल किए गए फाइबर, नई सामग्री, सस्टेनेबल पैकेजिंग और अन्य उच्च मूल्य वाले उत्पादों को बनाना है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल उत्पादन पद्धतियों के बढ़ते वैश्विक महत्व को देखते हुए, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना, रिसाइकलिंग और अपशिष्ट में कमी लाना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, बेहतर बाजार पहुंच, बेहतर पर्यावरणीय और आर्थिक रेजिलेंस और निवेशक के बढ़ते भरोसे के संदर्भ में उनके प्रत्याशित लाभों को देखते हुए कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

i) सरकार देश भर में सतत उत्पादन और खपत की वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए पायलट परियोजनाओं की एक श्रृंखला को आयोजित कर रही है, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर फोकस किया गया है:

- "फैशन आपूर्ति श्रृंखला से हानिकारक रसायनों का उन्मूलन" नामक एक परियोजना, यूएनआईडीओ के सहयोग से तथा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) की साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य भारत की अपैरल एवं फैशन आपूर्ति श्रृंखला से हानिकारक रसायनों का उन्मूलन करना तथा ऊर्जा एवं अपशिष्ट के उपयोग, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सहित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से सतत् पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के सहयोग से 'भारतीय वस्त्र क्षेत्र को सर्कुलेरिटी की ओर ले जाने को तेज करना' (इन-टेक्स इंडिया) को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए) और उत्पाद पर्यावरण पदचिह्न (पीईएफ) पद्धतियों का लाभ उठाकर सर्कुलर व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने पर फोकस करता है।

ii) वस्त्र अपशिष्ट के बढ़ते प्रभावों को कम करने के लिए, सरकार ने वस्त्र समिति, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) और गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित कई गतिविधियां शुरू की हैं ताकि सरकारी खरीद में अपसाइकल्ड उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

***